[A. C. George]

Corporation Mills, have been representing that these prices need upward revision in view of the currently increased cost of production. Government also have been anxious to increase the quantum of the controlled varieties of cloth.

Government have now formulated a revised policy to this end. The main features of this policy are that the quantum of controlled cloth will be increased from the present level of 400 million metres to 800 million metres per annum, and the varieties will now include the medium 'A' category of cloth also in the commonly used five varieties of sarees, dhoties, drill, shirting and longcloth. Even though costs of production have risen much higer it has been decided that an increase of only 30% over the May 1968, prices will be allowed. In order to safeguard consumer interests, selvedge printing of prices on every meter of cloth will be progressively introduced and the distribution machinery will be strengthened. The distribution margin has been provided at 20% of ex-mill prices to meet currently increased costs of transport and distribution. The penalty for non-fulfilment of controlled cloth obligation will be enhanced from the present level of Re 1/- per metre to Rs 2.50 per metre.

In the light of this enhanced obligation on textile mills to produce controlled cloth, suitable provision is being made in the Scheme to sustain the requisite export effort

The revised policy will be brought into effect from the 1st of April, 1974.

MR. CHAIRMAN : We now take up the Private Members' Business. Mr. Gomango.

16.10 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-EIGHTH REPORT

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput) : I beg to move :

"That this House do agree with the Thirty-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 27th March, 1974."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That this House do agree with the Thirty-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 27th March, 1974."

The motion was adopted.

16.11 hrs.

RESOLUTION RE : POLICY IN RESPECT OF PRICES AND AGRICULTURAL PRODUCTION—*contd.*

MR. CHAIRMAN : We now resume further discussion on the Resolution regarding prices and agricultural production. Mr. Madhu Limaye

SHRI MADHU LIMAYE (Banka) : The Resolution which I have already moved reads as follows :

"This House is of opinion that the Government should recast its policy with regard to prices and agricultural production in such a way that—

(a) essential articles of consumption sell at 1½ times the cost of production, including transport charges, taxes and profits,

(b) there shall prevail parity between the prices of industrial goods and agricultural produce;

(c) fluctuations in foodgrain prices of more than 15 per cent shall not be permitted;

(d) the Government shall take the responsibility of purchasing cotton, sugarcane, raw jute, foodgrains and other produce at support prices which may take into account the cost of production plus a reasonable margin for the farmers;

(e) electricity rate per unit for agricultural purposes shall not be more than ten paise; and

(f) fertilisers shall be made available to the *Kisans* with land holdings of less than ten acres at subsidised rates and the irrigation rates shall be reduced by 25 per cent."

मेरे कई लायक दोस्तो ने पिछली बार जब मजदूरों के एक मामले पर चर्चा हो रही थी तो यह कहा था कि इस भवन में जितना समय कारखानों मे काम करने वाले मजदूरो और कर्मचारियो के सवाल पर दिया जाता है उतना समय काश्तकारो की जो समस्याएं हैं उन पर बहस करने के लिए नही दिया जाता है। इसीलिये आज मैं देखूगा कि मेरे लायक दोस्तो का मेरे प्रस्ताव के बारे मे क्या रुख रहेगा क्योंकि इस प्रस्ताव का यह महत्व है कि यदि इसके सिद्धांतो को सरकार मान लेगी तो हमारे आर्थिक नियोजन की नीति में बुनियादी परिवर्तन आएगा और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर बनाने की दिशा मे बहुत बड़ा कदम हम उठाएगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस में जो सिद्धान्तिक बाते हैं उनकी ओर खीचना चाहता हू। सरकार ने विगत 27 वर्षों मे हमेशा ठोस बातें करने के बजाय साधारण बाते करने का जो एक सिलसिला चलाया है उसका नतीजा होता है कि किसी निष्कर्ष पर हम लोग नही पहुच पाते। सभी लोग कहते है कि दामों पर नियंत्रण होना चाहिए। जीवनावश्यक चीजे लोगों को उचित दामों मे मिलनी चाहिए, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मे चुस्ती आनी चाहिए यह विचार तो मंत्रियो के भाषणो मे हमेशा हम लोग पाते है। लेकिन इन चीजों का कार्यान्वियन क्यो नही हो रहा है, क्यों कि यह सरकार निश्चित और स्पष्ट सिद्धातो के साथ अपने को बाधना नही चाहती। यह हमेशा निर्गुण और निराकार ब्रह्म की चर्चा करना चाहती है। नतीजा यह होता है कि जो बुनियादी आवश्यकताए है उनको हम लोग पूरा नही कर पाते। क्या मंत्री महोदय इस बात से असहमति रखते हैं कि जो जीवनावश्यक चीजें हैं उनके दाम निश्चित करते समय विक्रय, मुनाफा और जो मैनेजरी का खर्चा होता है उस के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए; जीवनावश्यक चीजो की व्याख्या करते हुए पचास वस्तुओ का समावेश इस नही करना चाहता हूं। अगर सरकार चाहती है इसको सीमित ही रखा जाये। लेकिन इस मे दो राय नही होगी कि जैसे गल्ला है, कपड़ा है, चीनी है, केरोसिन है, तेल है, नमक है, ये चीजें ऐसी हैं कि जिनके बिना साधारण लोगो की जिन्दगी नही चल सकती। इसलिए कम से कम इन वस्तुओं के बारे में इस सिद्धान्त को लागू करने का प्रयास होना चाहिए और जब कपड़ा-नीति की हम लोग चर्चा करेंगे तो मुनाफे के ऊपर रोक लगनी चाहिए। टिक्स को कम कर देना चाहिए और दूसरे परिवहन आदि के जो खर्चे है उनमें भी कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कपड़ा, चीनी, तेल, केरोसिन, नमक, मिर्च आदि चीजे उत्पादन का जो खर्चा है उसके ड्योढे मे भी बेचने लगेंगे तो साधारण जनता को बहुत बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी, क्या कपड़ा, केरोसिन तेल, चीनी आदि के वर्तमान दाम सिद्धान्त न० 1 के अनुसार है, — जहा तक चीनी का सवाल है विगत साल चीनी मिलो की जितनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है उसके अनुसार जो बड़ी-बड़ी मिलें है उनके मुनाफे मे विगत साल बहुत बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। इसमे जो करो की चोरी वह करते हैं या 70 प्रतिशत चीनी आप नियंत्रित दामों पर खरीदते हैं लेकिन वास्तव मे मिलो से इतनी चीनी खरीदी नही जा रही है, एक मिल का उदाहरण है उसके बारे मे मैं खाद्य मंत्री को लिख चुका हू, उनको तो उनका जो लेवी शुगर का कोटा था उसी को खुले बाजार में बेचने की छूट दे दी गई .

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) ऐसा नहीं हो सकता।

श्री मधु लिमये . बिलकुल हो गया है।

[श्री मधु लिमये]

क्यों कि दोनों के बीच में इस वर्ष संघर्ष चल रहा है और बरेली की एक मिल है उस के बारे में मंत्री को लिख चुका हूं। तो 70 प्रतिशत लेवी की चीनी वसूली नहीं जाती। यह काम फूड कारपोरेशन आफ इंडिया पर छोड दिया गया है और बहुत दफा यह लेवी की चीनी ऊपर से नीचे तक खुले बाजार में चली जाती है और काले दामों में बिकती है।

जहां तक कपडे का सवाल है विगत साल मैंने स्वयं आकड़े दिए थे कि 1971 के जनवरी महीने से 1973 के जनवरी महीने तक कपास का दाम लगातार घटता जा रहा है और इन दो वर्षों में कपडे के दाम में कटौती होने के बजाय बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। उस का नतीजा है कि 1972-73 में जो भी बैलेंस शीट प्रकाशित हुई उन से पता चलता है कि जो बड़ी-बड़ी प्रमुख मिलें हैं खास कर के बड़े उद्योगपतियों की मिलें उनके मुनाफे में 11 से ले कर 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ये आकड़े मैंने स्वयं सदन के सामने रखे हैं। तो चीनी मिलों के द्वारा भयंकर मुनाफाखोरी, कपडा मिलों के द्वारा भी कर मुनाफाखोरी और कपडे के ऊपर, चीनी के ऊपर, केरोसिन के ऊपर आप लगातार टिकस भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि आज मंत्री महोदय इस आशय की घोषणा करें कि जहां तक जीवनावश्यक चीजों का सवाल है हम संयम बरतेंगे कर लगाते समय, मुनाफे पर भी नियंत्रण रखेंगे और कम से कम पाच छः चीजें जो मैंने बताई उन का दाम नियंत्रित कर के वितरण व्यवस्था में से भ्रष्टाचार और अकार्य-क्षमता को खत्म कर के सही ढंग से उनका वितरण कराएंगे।

दूसरा सिद्धांत मैं रखता हूं कि खेती के माल में और औद्योगिक माल में हम लोगों को संतुलन कायम करना चाहिए। इसके बारे में मैंने एक सवाल इसी सदन में पूछा था और उस का बहुत ही विचित्र जवाब खाद्य मंत्री से मुझे मिला था। मैंने इस संतुलन के बारे में जो कहा था उसके जवाब में मंत्री महोदय ने 23 जुलाई को कहा था:

> "In India prices of agricultural commodities have generally shown a relatively greater rise than the prices of manufactured goods. But the elements of speculation do play a large part in the trade of agricultural commodities."

अब मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—आप चीनी की ही बात को लीजिये—1668 में गन्ना उत्पादकों को उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में एक क्विंटल का 15 रुपया दाम दिया गया था और उस समय खुले बाजार में चीनी 2 रुपया या सवा दो रुपया किलो बिक रही थी। 1973-74 के मौसम में उत्तर प्रदेश के इलाके में साधारण तौर पर सवा-तेरह रुपये क्विंटल के हिसाब से गन्ना उत्पादकों से लिया गया। कहीं कुछ कम और कहीं कुछ ज्यादा, 13 रुपए के दाम भी दिए गए और साढ़े तेरह रुपए के दाम भी दिये गये, लेकिन औसत में सवा तेरह आयेगा। लेकिन खुले बाजार में चीनी का दाम क्या है? सवा चार से साढ़े चार रुपए किलो के हिसाब से चीनी बिक रही है।

जब शिण्डे साहब कहते हैं कि भारत में कृषि का जो उत्पादन है उसके दाम में, कारखानों में या मिलों में पैदा होने वाली चीजों के दाम के मुकाबले अधिक तेजी से वृद्धि हुई है—तो मुझे दुख होता है। आम चीनी का ही उदाहरण ले लीजिये। आपको पता चल जायेगा कि यह सही नहीं है। चीनी में किसानों को जो भी मूल्य आपने बताया है, उसको घटाने के बाद भी चीनी की जो बिक्री की दर है उसके बढ़ने का क्या कारण है, उसका दाम सवा चार रुपए में क्या हुआ मैं 1968 के खुले दाम और इस समय के खुले दामों की चर्चा कर रहा हूं।

इसी तरह कपड़े की स्थिति है । पिछले 5-6 महिनों में कपास के दामों की स्थिति जरूर बदली है, लेकिन जितना हल्ला किया जा रहा है किसानों को बहुत लाभ हो रहा है—वह स्थिति नहीं है । मेरे सामने यह "कामर्स साप्ताहिक" है, इसमें प्रो० दंतवाला का एक लेख है—"पोलिटिक्स एण्ड प्राइज़" । इन्होंने इस लेख में कृषि दाम नीति की घोर आलोचना की है, इनका यह कहना है कि काश्तकारों को बहुत ज्यादा दाम दिये जा रहे हैं । लेकिन अभी कुछ ही समय पहले 'इकानिमिक टाइम्ज़' में कपास के बारे में जो खबर आयी थी उसमें यह कहा गया था—

"The cotton prices have fallen by Rs. 100 to Rs. 250 per candy owing to heavy arrivals of cotton on the one hand and slackening of demand from the buyers on the other."

यह बात 7 मार्च के इकानिमिक टाइम्ज़ में कही गई है । इसलिये यदि 3 साल के आंकड़े इकठ्ठे किये जाएं तो इसमें दो राय नहीं होंगी कि कपड़े के दामों में अधिक तेजी से वृद्धि हुयी है, बनिस्पत कपास के दामों के । इसमें भी कपास के दाम लेते समय मैंने उस दाम को नहीं लिया है जो सट्टा वगैरह चलता है या जो इज़ारेदारी चलती है उससे जो दाम बढ़ जाता है, उसको लेने से कोई फायदा नहीं है । मैं इस समय उसी दाम की चर्चा कर रहा हूं कि कपास का किसानों को क्या दाम मिला और कपड़े का उपयोगी—मूल्य क्या है, जिस पर कि साधारण उपभोक्ता को देना पड़ता है । यदि इसका तीन साल का तुलनात्मक अध्ययन किया जायगा तो निश्चित रूप से साबित होगा कि कपड़े का दाम अधिक मात्रा में बढ़ा है और उस अनुपात में रूई और कपास का दाम नहीं बड़ा है ।

इधर मैंने बजट पर बोलते समय इस बात को छेड़ा था कि लम्बे धागे की रूई आप इजिप्ट, सूडान, से मंगवा रहे हैं । तब वित्त मंत्री जी ने कुछ गर्मी में कहा—पहले हम मंगवाते थे, लेकिन सबने इन दिनों लांग स्टैपल काटन मंगवाना बन्द कर दिया है । ऐसा लगता है कि वित्त मंत्रालय और व्यापार मंत्रालय में कोई एकसूत्रीकरण नहीं है, क्योंकि व्यापार में मंत्रालय ने मेरे ही प्रश्न के उत्तर में कहा है —

"Cotton year 1970-71, imports 8.51 lakhs bales value in crores of Rupees 109.85 crores."

यह 1970-71 का आप का आयात है । उसके बाद 1971-72 में 7 लाख 44 हजार बेल्ज़ मंगवाई और उस पर 101 करोड़ 73 लाख रुपए की देशीविदेशी मुद्रा खर्च की । 1972–73 में आप ने 4 लाख 42 हजार बेल्ज़ मंगवाई जिस पर 64 करोड़ 90 लाख रु० की विदेशी मुद्रा आप ने खर्च की । जहां तक 1973-74 का सवाल है, मेरी जानकारी है कि आपने 4 लाख बेल्ज़ मंगवाई हैं । मने पूछा था कि यह जो लम्बे धाग की रुई मगवाते हैं, क्या इस का निर्यात के लिये इस्तेमाल होता है या हिन्दुस्तान के जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनके शरीर पर बढ़िया वस्त्र चढाने के लिये इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्यापार मंत्रालय ने जवाब दिया —

"About 10 to 11% of the cloth made out of the yarn produced from the imported long staple cotton has been exported this year."

यानि 10 से 11 प्रतिशत । इस आंकड़ों के बारे में मुझे संदेह है कि क्योंकि, इनको यह कैसे पता चला कि आयातित रूई से जो कपड़ा बनाया गया , उसी को निर्यात किया गया, क्योंकि भारत में लम्बे धागे की कपास पैदा होती है । आपने इतनी बड़ी रकम विदेशी मुद्रा के रूप में इस लम्बे धागे की कपास को मंगवाने में खर्च की है अमीरों को अच्छा कपड़ा देने के लिये आप ने खर्च की है—मैं जानना चाहता हूं कि इस नीति के पीछे कौन सा सिद्धांत है । क्या यह समाजवाद की नीति है या अमीर, उच्च वर्गीय, उच्च वर्गीय नीति है—इसका

[श्री मधु लिमये]

फैसला सदस्य लोग करें । इसके लिये मैं कहना चाहूंगा कि यह जो दूसरा सिद्धांत है कि खेती का माल और कारखानीय माल—इनके बीच संतुलन होना चाहिए, समाजिक न्याय की दृष्टि से आप को इस सिद्धान्त को कुबूल करना चाहिए ।

आगे मैंने कहा है कि गल्ले के दाम में एक साल में 15 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए । आप ने कई प्रश्नों के जवाब में कहा है कि कहीं कहीं ये दाम बढ़े हैं । बाजरा है, मक्का है, आप ने यह माना है कि एक महीने में 20-25 और 30 प्रतिशत तक परिवर्तन हुआ है और पूरे साल की बात तो आप जानते ही हैं । जब कटनी का समय आ जाता है तो किसान अपना माल मंडी में लेकर आता है, तब दाम गिर जाते हैं और जब उसे स्वयं खरीदने की नौबत आती है, यानि लीन-मंथ्स में, उसकी नई फसल आने से पहले, तो जिस भाव उसने बेचा होता है, उससे 50-60 अधिक दाम देकर खरीदना पड़ता है । इसके लिये गल्ले के दाम में 15 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए । 15 प्रतिशत इसलिये रखा गया है कि स्टोर करने का खर्चा होगा, बैंकों से कर्जा लिया है तो उसका सूद देना होगा—इसलिये मैं 15 प्रतिशत की बात कर रहा हूं ।

चौथी बात यह है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कृषि का जो माल है, वह निर्धारित दामों पर सरकार खरीदे । अब इसमें आप राष्ट्रीयकरण करें या निजी क्षेत्र में उसका व्यापार रहने दें—इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस बारे में मेरी निश्चित राय है कि चाहे राष्ट्रीयकरण की नीति हो या निजी व्यापार की नीति हो, जब तक प्रशासन में भ्रष्टाचार और बेइमानी रहेगी, वितरण व्यवस्था में घूसखोरी चलेगी, तब तक आप की दोनों नीतियां असफल रहने वाली हैं । इस साल आप दूसरी नीति चलाने जा रहे हैं इसका भी अनुभव ले लीजिए । क्योंकि इस के बारे में मेरे पास अभी अभी दो पत्र आये हैं, उनसे आप को पता चल जायगा कि भ्रष्टाचार की आज स्थिति क्या है । एक पत्र मुझे बलरिया प्रखंड से, जो मेरे क्षेत्र में है, मिला है । उसमें उन्होंने सबूत के साथ साबित किया है कि कि आप के जो सब इंसपेक्टर्स होते हैं—जब पिछली बार मैं गया था तो मुझे कहा गया था—एक बोरा गेहूं देने के लिये सप्लाई इंसपेक्टर 5 रु० घूस लेता है चीनी के ऊपर 15 रु० लेता है, किरासिन के एक ट्रक पर 15 रु० लेता है । लेकिन पिछले दो तीन महिनों से जैसे जैसे दाम बढ़े हैं घूस खोरी की दर भी बढ़ती गयी और अब घूसखोरी की दर ही गयी है—गेहूं के बोरे पर 10 रुपया, किरासिन ट्रक पर 25 रुपया, चीनी के बोरे पर 25 रुपया । खुद डीलर कहते हैं कि जब तक इस तरह की घूस हम नहीं देंगे हम को माल नहीं मिलेगा और घूस देकर माल लेंगे तो सप्लायी इंसपेक्टर कहता है कि कोई जरूरी नहीं कि गरीबों को बेचो, ज्यादा दाम बढ़ाकर बेच सकते हो, डायरी या रजिस्टर को रेग्यूलराइज कर दूंगा । पास कर दूंगा तीन बार आंचल अधिकारी ने जांच के लिये उस डीलर को बुलाया, लेकिन वह नहीं आया और जांच नहीं हो पायी ।

यहां हम लम्बे चौड़े लेक्चर दे रहे हैं कि गल्ले का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, या निजि व्यापार होना चाहिए, लेकिन सभी मानते हैं कि समाज में जो शोषित तत्व है, जिनके पास अपनी खेती बाड़ी नहीं है और अगर है तो मामूली है, उन लोगों तक सार्वजनिक व्यवस्था में न्यूनतम गल्ला नहीं मिलेगा, वे जिन्दा नहीं रह सकते । तो सभी लोग मानते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था रहनी चाहिए और उसके मार्फत ऐसे तत्वों को कम से कम गल्ला मिलना चाहिए । लेकिन वितरण व्यवस्था में इस तरह की बेइमानी रहेगी तो क्या होगा ?

अब आप लेवी की बात कीजिए । लेवी के बारे में इस तरह के सुझाव होते हैं । मेरे क्षेत्र से मुझे पत्र मिला है जिसमें कहा गया

क बिना नोटिस के उन्होंने 20 क्विंटल धान लेवी के रूप में वसूलने के लिए कहा। छोटे किसान की बात थी, उसके पास उतना धान नहीं था तो उन्होंने कहा कि 500 रु० घूस दीजिए तो आपको लेवी देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं लेवी का विरोधी नहीं हूं आप इस गलत फहमी में न आयें। एक ओर जब मैं चाहता हूं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को गल्ला मिले, कम से कम ऐसे गरीब लोगों को, भूमिहीनों को और शहर के गरीब लोगों को तो सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था के लिये गल्ला कहां से आयगा मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं कि आप लगातार विदेशी आयात करते चले जायें। इसलिये गल्ला तो आपको प्रक्योर करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप यह लेवी की प्रणाली को चलाते हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि यह भी एक लेवी की प्रणाली चलायी है जो होल सेलर्स पर लेवी लगायी जायेगी चावल के बारे में या गेहूं के बारे में। पहले आप सीधे वसूलते थे। मेरा कहना है कि छोटे किसानों के उपर जुल्म न हों जिस तरह इनकमटेक्स में बड़े लोग जिनकी आमदनी ज्यादा है उससे आप ज्यादा टैक्स वसूलते हैं हालांकि इस बार इस सिद्धांत को भी आपने छोड़ दिया है। छोटे लोगों को आपने कम राहत दी है और बड़ी आमदनी वालों को आपने ज्यादा राहत दी है, इस आशा से कि वे करों की चोरी नहीं करेंगे। तो मैं यह कह रहा था कि जिनके पास अतिरिक्त अनाज है मण्डी में बेचने लायक उनके ग्रेडड लेवी के आधार पर आप लेवी जरूर वसूलिये—मैं इसका विरोध नहीं करूंगा लेकिन आप जो बड़े काश्तकार हैं जो लेवी में अनाज दे सकते हैं उनसे आप अनाज वसूलते नहीं हैं और जो छोटे लोग ह, आपकी मशीनरी इतनी सड़ गयी है कि मार उन छोटे लोगों पर पड़ती है। मैं केवल इसकी चर्चा कर रहा हूं कि निर्धारित दामों से सरकार खरीदे, अगर दाम नीचे जायेंगे तो आपके पास लोग आयेंगे और छोटे लोगों को अगर ज्यादा दाम मिल जायगा तो कोई बुरी बात नहीं है।

जूट के बारे में आपने आश्वासन दिया था कि एक सौ साढ़े 57 रुपए क्वींटल के हिसाब से कलकत्ता डेलिवरी का जूट आप लेंगे लेकिन आप बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में, उत्तरी बिहार में जाकर देखें क्या काश्तकारों को जूट का वह दाम मिला, तो आपको पता चलेगा कि बड़े ग्रोवर्स को छोड़कर छोटे ग्रोवर्स को किसी हालत में नहीं मिला है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आपने क्या लक्ष्य बनाया है? आपने यह लक्ष्य बनाया है:

> "The rate of growth of output in the agricultural sector envisaged for the Fifth Plan period is 4.67 per cent per annum. The fulfilment of this target will make the country not only self-sufficient in respect of foodgrains but also leave a cushion for building a buffer stock."

तो 4.67 परसेन्ट की दर से अगर कृषि का आप का विकास करना चाहते हैं तो कृषि के लिये आपकी कोई योजना होनी चाहिए जिसका मैं कोई प्रकाश चिन्ह नहीं देख रहा हूं—मुझे अफसोस है। हमारी योजना बनाने वाले अधिकारी लोग हैं, मैं किसी में में फर्क नहीं करना चाहता, बेकारी निराकरण के बारे में उनकी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं मेरी यह निश्चित धारणा है कि बेरोजगारी की जो भयंकर समस्या है उसका यदि समाधान करना है तो तथाकथित औद्योगीकरण के जरिये वह कभी नहीं होगा बल्कि कृषि विकास के ऊपर आप जोर देंगे तो बेकारी की समस्या का भी समाधान होगा। इतना ही नहीं, औद्योगीकरण के लिये भी रास्ता प्रशस्त हो जायगा।

मैं एक उदाहरण देता हूं। मुंगेर जिले में जो ताल का इलाका है उसमें यदि आप योजना का इन्तजाम कर दें और बोरिंग आदि का प्रबंध करेंगे तो निश्चित रूप से दो फसलें निकाल पाएंगे। मक्का की फसल निकाल पायेंगे और एक रबी की फसल निकाल पायेंगे। नतीजा यह

[श्री मधु लिमये]

होगा, मैं उत्तरी बिहार की बात नहीं कह सकता लेकिन मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना इन इलाकों में जितने ग्रामीण बेकार लोग हैं इन सभी को अकेली इस योजना में काम मिल जायगा। इसलिये यदि बहुत बड़े पैमाने पर बेकारी की समस्या का आप हल करना चाहते हैं तो कृषि विकास योजनाओं पर आपको जोर देना पड़ेगा और उसी में से आपको पूंजी भी मिल जायगी। इन बातों को लेकर मैं कहता हूं कि कि आप कृषि के विकास के लिए समुचित प्रयास नहीं कर रहे हैं और कृषि विकास से जिनकी समुचित आमदनी हो रही है उन पर आप टैक्सनहींलगाते हैं। मैं कहता हूं कि आमदनी बढ़ाने के लिए आप उत्पादन बढ़ाने का समुचित प्रयास कीजिए। उससे अधिक लाभ जिनको होगा उनपर जैसे कि अन्य आमदनी पर आप टैक्स लगाते हैं कृषि आमदनी पर भी टैक्स लगाइये या एक्रेज की बेसिस पर इनकम टैक्स लगाइये जिसमें बेइमानी और घूसखोरी की कम से कम गुंजाइश होगी। तो इस रास्ते को आप अपनाइये। इसलिये मैंने सुझाव भी दिया है —

Electricity rate per unit for agricultural purposes shall not be more than 10 P

अब आपकी क्या प्रायर्टीज है, वरीयता के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है यह मैं जानना चाहता हूं। मैं भी जानता हूं आज एल्यूमिनियम की हमारे देश के लिये आवश्यकता है लेकिन हिंडालकों वे कर्मचारियों ने मुझको आंकड़े दिये हैं कि 55 मेगावाट का जो पुराना करार है उसकी वजह से पैसे की यूनिट से भी कम आप हिंडालकों से वसूलते हैं। 50 मेगावाट का जो नया समझौता हुआ है उसमें आपने 10 पैसे की यूनिट दाम रखे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कृषि उत्पादन को वरीयत आप एल्यूमिनियम या निजी क्षेत्र से कम देते हैं? आप इस बात का बिलकुल फैसला कीजिए कि आने वाले कुछ वर्षों के लिए बिजली का प्रति यूनिट का दाम कृषि कार्य के लिये 10 पैसे से अधिक नहीं रहेगा। यह आपको एकदम निर्णय करना चाहिए

इसके साथ साथ मैं जो अंतिम प्रस्ताव रखना चाहता हूं वह यह है कि इस एकड़ वाले किसान इधर चार पांच साल की रबी की ओर अधिक अभिमुख होने लगे थे, अच्छा बीज भी इस्तेमाल करने लगे थे और खाद का भी प्रयोग करने लगे थे लेकिन इस बीच आप खाद का दाम भी बढ़ाते जा रहे हैं और उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ाते जा रहे हैं। खाद के वितरण में इतनी बेइमानी है कि नियंत्रित जो दाम है बिहार में साढ़े बावन रु० यूरिया के बड़े बोरे था लेकिन दो महिने पहले वह 100 रु० में मिलता था और इस बारे में जब मैं गया तो लोगों ने कहा कि हम 5 रुपया किलो के हिसाब से खाद खरीदते हैं। (व्यवधान) इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप छोटे किसानों को, अपना जो घाटा है उसको सहते हुए नियंत्रित दाम से भी कम दाम पर खाद देने का प्रबंध कीजिए और इस वक्त जो सिंचाई का रेट अनाप शनाप बढ़ाया जा रहा है, सिंचाई के ऊपर टैक्स लगाकर आर्थिक नियोजन के लिये आप पैसा लेने की बात करते हैं उसको भी बन्द कर दीजिए मैं आप को उल्टी बात कहता हूं कि आप सिंचाई कर कम कर दीजिए आप फर्टीलाइजर का दाम घटा दीजिए, और किसानों को जो आमदनी हो उसके आधार पर टैक्स लगाइये। आप उत्पादन को ही मारने की बात क्यों करते हैं। आप सामाजिक न्याय की बात क्यों करते हैं तो आमदनी संबंधी कर नीति आपकी होनी चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जैसे कि प्रोफेसर लोग अक्सर इस सदन में कहते हैं कि हमारी आमदनी संबंधी नीति कोई सामाजिक न्याय नहीं है। मैंने एन० आई० सी० के तीसरे और चौथे श्रेणी के कर्मचारियों की कुल मिलाकर आमदनी का आंकड़ा निकाला है जो कि साढ़े आठ हजार रुपया प्रति वर्ष आता है। इसमें मैं सारी एमिनिटीज शामिल कर ली है। लेकिन कितने किसान आज हमारे देश में हैं जिनकी साढ़े आठ हजार की नेट इनकम प्रतिवर्ष हो जाती है। क्लास टू और

क्लास वन के अफसरों के आंकड़े भी मैंने निकाले हैं जोकि एक लाख 32 हजार होता है। एल० आई० सी० में ज्यादा आमदनी होती है तो उसको आप घटाएं लेकिन तीसरे और चौथे वर्ग के कर्मचारियों की आय की भी जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे एसा लगता है कि छोटे किसानों के बारे में सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है; इसलिये पहले सामाजिक न्याय को लाने की दृष्टि से उत्पादन जिससे घटेगा या ज्यादा फसलें निकालने के कामों की ओर से किसान मुड़ जायेंगे इस तरह की आप की टैक्सेशन नीति नहीं होनी चाहिए।

फर्टिलाइजर के ऊपर ऐक्साइज ड्यूटी लगाने की बात, एनर्जी टैक्स बढ़ाना, इलेक्ट्रिसिटी की दर बढ़ाते हैं, इन तमाम कामों से उत्पादन खत्म हो जाता है। इसलिए केवल बड़े किसानों पर उनकी आमदनी के अनुपात में अगर टैक्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिये आप संविधान में परिवर्तन ले आते। इतने परिवर्तन आप ने किये, क्योंं नहीं इस तरह का परिवर्तन ले आते कि बड़े काश्तकारों पर टैक्स लगाने के लिये राज्य सरकारों को बाध्य कीजिये। वह टैक्स आप न लीजिये। लेकिन आप संविधान में परिवर्तन कर के उस का अनुपात तय कर दीजिये, और राज्यों को वसूल करने के लिये कहिये, और उन को यह भी कहिये कि इस तरह के टैक्ससेशन से जो आमदनी उन को मिलेगी उस में मैचिंग ग्रान्ट हम देंगे और उस का एक फंड बनाइये जिस का इस्तेमाल जो आज असिंचित इलाके हैं उन के लिये कीजिये। महाराष्ट्र की बात मंत्री जी जानते हैं महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सवाल है कि कुछ लोगों को तो 12 माही सिंचाई मिलती है और कुछ लोगों को दो महीने के लिये भी सिंचाई नहीं मिलती है। तो यह जो फंड है इस पैसे का इस्तेमाल आप असिंचित इलाकों में सिंचाई का फैलाव करने के लिये कीजिये। इस तरह की उत्पादन बढ़ाने वाली, सामाजिक न्याय लाने वाली, कृषि को प्रोत्साहन देने वाली योजनायें आप बनायेंगे तो निश्चित रूप से जो वर्तमान कुंठा अर्थ व्यवस्था में पैदा हो गई है यह खत्म हो जायगी और देश तेजी से तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगा।

नीतियों का जहां तक सवाल है, सब से बुनियादी सवाल हो गया है भ्रष्टाचार, घूसखोरी और सरकारी यंत्र के शुद्धीकरण का। आप लाख कहिये, नीतियां बनाइये, विदेशों से विशेषज्ञ ले आइये, डाक्टर ले आइये, यह बीमारी जाने वाली नहीं है जब तक इस यंत्र का शुद्धीकरण नहीं करेंगे और कठोर आदेश नहीं करेंगे। और इसके लिये मैं छोटे सप्लाई इंस्पेक्टर की चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि प्रधान मंत्री, मंत्री, गवर्नर और संसद सदस्य और विधान सभाओं के सदस्यों से आदर्श पेश कया जाय, तब जा कर नीचे तक शुद्धिकरण का सिलसिला प्रारम्भ होगा। चीन ने अपना कल्चरल रिवौल्यूशन किया, हमारे देश में भी शुद्धिकरण की क्रान्ति की जरूरत है। और आज लड़कों के मन में यह बात आ ईगई है कि आप गोली के बल पर इस आन्दोलन को नहीं दबा सकते, बल्कि वह सोचते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाये बिना हमारी तरक्की नहीं होगी। इसलिये इन सुझावों पर आप विचार कीजिये, यही मुझे कहना है।

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:

"This House is of opinion that the Government should re-cast its policy with regard to prices and agricultural production in such a way that—

(a) essential articles of consumption sell at 1½ times the cost of production, including transport charges, taxes and profits;

(b) there shall prevail parity between the prices of industrial goods and agricultural produce;

(c) fluctuations in foodgrain prices of more than 15 per cent shall not be permitted;

[Mr. Chairman].

(d) the Government shall take the responsibility of purchasing cotton, sugar-cane, raw jute, foodgrains and other produce at support prices which may take into account the cost of production plus a reasonable margin for the farmers;

(e) electricity rate per unit for agricultural purposes shall not be more than ten paise and

(f) fertilizers shall be made available to the Kisans with land holdings of less than ten acres at subsidised rates and the irrigation rates shall be reduced by 25 per cent."

There are some notices of amendments. Members who are desirous of moving them may move them Shri Bibhuti Mishra—absent. Shri B. K. Daschowdhury.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar). I move.

'That in the resolution in part (a),—

for "essential articles of consumption sell at 1½ times" *substitute*—

"all essential agricultural produce sell at 1½ times"

(2)

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) I move:

'That in the resolution,—

add at the end—

(g) the Government should establish its decisive command over the production and distribution of vital agricultural commodities and agricultural inputs;

and therefore, recommends nationalisation of Sugar Industry, raw jute trade, fertiliser production and distribution of diesel and kerosene oil with immediate effect"' (3)

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : मान्यवर, माननीय लिमये जी ने जो प्रस्ताव सदन में पेश किया है, काफी व्यापक और लम्बी चौड़ी भूमिका रखने वाला प्रस्ताव है। इस में कंज्यूमर से ले कर प्रोड्यूसर तक और बीच में सारे समाज में कुछ सिद्धान्तों को अपना कर उन्होंने क्रान्ति करने का सुझाव दिया है। मैं उन की भावना से बहुत हद तक कुछ बातों में सहमत हूं। पर जो उन्होंने मुद्दे रखे उन से मैं सहमत नहीं हूं, और उन के और मेरे दृष्टिकोण में अन्तर है। बुनियादी तौर से जो उन का ख्याल है कि अगर हमें देश में लोकतन्त्र के जरिये विकास और तरक्की करनी है और देश का उत्पादन बढ़ाना है, चाहे कृषि का हो या उद्योग का और सामाजिक न्याय देना है देश के सब लोगों को जिन को इस न्याय की जरूरत है, तो हमें परिवर्तन करने पड़ेंगे। और खासतौर से अभी जो उन का प्रस्ताव है उसमें उन्होंने परिवर्तन की बात कही है कि हमारी हाट बाजारी व्यवस्था में और उस के साथ में किसान को उस की पैदावार के कैसे उचित दाम दिये जाये और कंज्यूमर्स को भी वह चीजें वाजिब दामों पर मिल सकें इस के लिये उन्होंने ज्यादा कीमत बतायी है, सारे टैक्स मिला कर किसी कंज्यूमर को बुनियादी चीजें मिलनी चाहिये। और उस के बाद किसान को भी कुछ ऐसे दाम मिले जिसमें उस का उत्पादन करने का जो खर्चा पड़ता है उस में उस का मुनाफा शामिल हो। ऐसी प्राइस किसान को गारन्टी की जाय और उपभोक्ता को भी जरूरत की चीजें उन को दी जायें। मैं बुनियादी तौर से उन से सहमत हूं और यह सिद्धान्त हम को मानना चाहिये और अगर अपनी योजनाओं को कामयाब बनाना है और जो लक्ष्य रखे गये हैं, फिजिकल और फाइनेंशियल, उन को अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से हमें कीमतों के ऊपर, हाट बाजारी व्यवस्था के ऊपर से उन में टिकाऊपन हो, यह सारी व्यवस्था योजना के पहले देखनी पड़ेगी, और यह व्यवस्था किस प्रकार से चले उस के बारे में हमें जो संगठन बनाने की आवश्यकता है वह भी बनाने पड़ेंगे और किसान की पैदा की हुई चीजों की बुनियादी तौर से कीमत इस तरह तय करनी पड़ेगी जिससे उस को अपनी पैदावार बढ़ाने का उत्साह मिले।

एक बात पर मैं ज्यादा जोर देना हू, जिसे सरकार भी मानती है कि यह देश कृषि प्रधान देश है, 75 फीसदी लोग यहा कृषि पर आधारित हैं, जमीन से, पशु और कृषि से सबधित चीजो से इस देश का धन उत्पादन करते है तो ऐसे देश मे कृषि को सब से ज्यादा महत्व देना चाहिए। कृषि में सब से यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे कृषि के जरिये पैदा होने वाली चीजो के उत्पादन को बुनियादी तौर से बढायेंगे तभी इस देश का भला हो सकता है और फिर उन सारी चीजो से जो औद्योगिक उत्पादन हो वह सारी चीजे इस पहली बुनियादी भूमिका को पूरा करने के बाद फ्लो इन करती है। यह दृष्टिकोण सरकार भी सोचती है और अपनाने की जरूरत है। और उस पोइट को मैं नही कहूगा जिस को बजट के समय मे न कहा कि अभी भी हम को इस देश मे कृषि के लिये बहुत कुछ करना है, लेकिन जो उत्पादन का सारी इकोनामिक ग्रोथ का लक्ष्य रखा है 5 5 और कृषि का 4 67 और उसके लिये जो इन्वेस्टमेंट आप ने तजवीज किया है बुनियादी तौर से वह कम है, उस को ज्यादा किया जा सकता है। आज तो हम कृषि के अन्दर उत्पादन करने मे एक ऐसे मोड पर हैं जिसकी तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हू। जब इस देश के अन्दर काम पैदा हो रहा है, उस की डिमान्ड बहुत बढ़ गई है फर्टिलाइजर के साथ मे प्रोडक्शन जुडा हुआ है ऐनर्जी क्राइसिस है किसानो के पास जो ट्रेक्टर है, या ऐनर्जी का उपयोग बिजली के रूप मे करते हैं उस के लिये भी कोई प्रायरिटी नहीं है। यू० पी० मे चुनाव के दौरान मे न देखो कि तीन तीन दिन मे तीन घन्टे बिजली एक ट्यूबवैल पर मिलती थी। तो एक तरफ बिजली की कमी है, डीजल और क्रूड की कमी है क्रूड के दाम तिगुने हो गये हैं, डीजल किसान को मिलता नही, 20 लिटर से ज्यादा डीजल देते नही किसान को एक दफा, तो 20 लीटर डीजल मे ले कर किसान जब तक खेत पर पहुचता है तब तक वह खत्म हो जाता है। तो फर्टिलाइजर नही, डीजल नही, क्रूड नही, ऐनर्जी नही, फिर हम क्या कह सकते हैं किसान को कि वह अपना उत्पादन बढाये। इन चीजो की किसान को कमी है। क्रूड की मुसीबत दुनिया की है केवल भारत की ही नही फिर कैसे कृषि उत्पादन का बढावा दिया जाय। डीजल और क्रूड का प्रायरिटी पर कैसे उपयोग करें, सीजन मे जो चीजें किसान को चाहिये वह कैसे मिले इस के बारे मे सोचना पडेगा। किस प्रकार उस का समय पर आवश्यकतानुसार खाद दी जाय। जितनी खाद आप बाहर से ला रहे हैं वह मामूली है। इस साल जितना फर्टिलाइजर आप ने कन्जूम किया है 28, 29 लाख टन उस के मुकाबले अगली साल 38 लाख टन की व्यवस्था करने जा रहे है, जब कि माग 60 मे 60 से 80 लाख टन की है। तो फर्टिलाइजर के सही वितरण की व्यवस्था करना किसान को समय पर उस के काम आने वाली चीजे मिले जिन के जरिये ग्रीन रिवोल्युशन हो सकता है उन के समय से पहुचाने की व्यवस्था करना नितात आवश्यक है जिस से ग्रीन रिवोल्युशन हो सके। इन तमाम चीजो के जरिये उत्पादन बढ सके और बढे हुए उत्पादन का वाजिब दाम किसान को मिले यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है और इस पर अमल करना आवश्यक हो गया है।

आप दई को लीजिये। दई का दाम कम रहता है जब कि कपडे का दाम कन्जूमर को ज्यादा देना पडता है। प्रौफिट का काफी मार्जिन बीच के लोग खा जाते है। उस मार्जिन को कम कर के किसान और कन्जूमर को लाभ मिल सके इस के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था को बदलने का इरादा रखते हैं? अगर हम कुछ बुनियादी चीजो की कीमतो को अपने सगठनो की मार्फत और अपनी व्यवस्थाओ की मार्फत निर्धारित करे, तो अच्छा होगा। इन्होंने उन की कुछ बुराइयो की तरफ जोर

[श्री नाथू राम मिर्धा]

दिया, हम जानते है कि उन में कुछ बुराइयां है, कुछ खराबिया हैं लेकिन हमे यह देखे कि कि जितने सगठन बनाए जाएं, वे ठीक ढंग से चले। आज वे ठीक ढंग से चल नही पाते है और उन के अन्दर बहुत ज्यादा खराबिया पैदा हो जाती है। तो आवश्यकता यह है कि हम उन मे कुछ सुधार करे। हम अपनी तरफ से प्राइस स्ट्रक्चर को तय करे और किसान जिन चीजो को पैदा करता है चाहे वह गन्ना पैदा करे, चाहे वह कपास पैदा करे, उस की कीमतों को तय करे। कार्पोरेशन बनाने को हम ने अपनी प्लान के अन्दर स्वीकार किया और आप ने उन सब को पाचवी पच वर्षीय योजना मे लागू करने को कहा है। उन आर्गेनाइजेशन्स को बना कर हम किसान को उस की पैदावार का उचित दाम दो चाहे वह गन्ना हो, चाहे कपास हो, चाहे तिलहन हो और चाहे वह फूड ग्रेन्स हो। उन सारी चीजो के, दामो का निर्धारण हम उस को लागत का हिसाब लगा कर करे और उस को उस का मुनासिब मुनाफा दे कर, उस के कास्ट आफ प्रोडक्शन को देख कर, उस की चीजो को खरीदे और फिर उद्योग मे काम आने वाली चीजो को भी हम फिक्सड दामो पर दे। फिक्सड प्राइस के ऊपर ही वह मजदूरो को अपना मुनाफा छोड कर मिले और कन्ज्यूमर्स को भी ज्यादा पैसे न देने पड़े। इस प्रकार की एक पिक्चर बना कर हम एक कल्पना करे और उस कल्पना को पाचवी योजना मे साकार रूप दे कर योजना को जमाना बहुत जरूरी बात है। इस काम को हमे पांचवी योजना के अन्दर कर लेना चाहिए क्योंकि पहले की पचवर्षीय योजनाओ मे हम ने इस पर ज्यादा ध्यान नही दिया। उन मे कुछ चीजों पर हम ने ध्यान दिया था जिस की वजह से इतने उतार चढाओ हम ने देखें, लेकिन इतनी भयंकर स्थिति उन योजनाओ मे नही थी, जो भयंकर स्थिति हम पांचवी योजना मे देख रहे हैं। इस पांचवी योजना में स्थिति बहुत भयकर है और हर महीने प्राइस इन्डैक्स कितना बढ रहा है और क्या हालात हो रहे हैं, इन सब बातो को देख कर हमें गम्भीरता-पूर्वक इन मुद्दों पर सोचना चाहिए।

मै नही कहता कि आप किसान को 10 पैसे के अन्दर एक यूनिट बिजली दीजिए। आज कई राज्यो में 12 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली दी जाती है। आप बिजली के लिए दो पैसे प्रति यूनिट और ले लीजिए। इस मे छोटे किसानो के बारे मे शुरू मे इन्वेस्ट-मेन्ट का सवाल जरूर आता है। मेरा कहना यह है कि जो बहुत से छोटे किसान है, उन के लिए क्रेडिट की व्यवस्था हो। उन के आर्गेनाइजेशन्स ग्राउन्ड लेविल पर बने और और इन्वेस्टमेंट के लिए भी उन के पास पहले से साधन हो जिस से उन को फर्टिलाइजर्स और बिजली मिल सके। इरीगेशन रेट्स के बारे मे जो उन के विचार है, मै उन से सहमत नहीं हू। आप एक बात देखिये। आज एक कुए से एक किसान जो सिचाई करता है, तो एक एकड भूमि के लिए इरीगेशन का कास्ट करीब डेढ सौ रुपये आता है और केनाल से जब वह इरीगेशन करता है तो उसी एक एकड मे उस का कास्ट करीब 15 20 रुपये आता है . व्यवधान कही कही पर 30 रुपये भी आता है। यह तो आप आप पर निर्भर करता है। इस तरह से आप देखे कि केनाल इरीगेशन रेट्स जो है वे बहुत कम है और मै उन की इस बात से सहमत नहीं हू कि केनाल के इरीगेशन रेटस बढाने की कोई गुजाइश नहीं है। मै ऐसा समझता हू कि केनाल के इरीगेशन रेट्स को बढाया जा सकता है। कही पर जहा इरीगेशन रेट्स बहुत ज्यादा पडते है, उन के मुकाबले में केनाल इरीगेशन वालो का पैदावार करने का तरीका बहुत ज्यादा सस्ता है और इसलिए मेरा निवेदन है कि इस को देखा जाना चाहिए। अगर बिजली के रेट्स ज्यादा बढाएंगे, तो कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसलिए इन सारी चीजो मे क्या बैलेंस हो, इस चीज को आप को देखना चाहिए।

आज गन्ने के दाम किसानो को देने के लिए जो व्यवस्था मिलों के लेबिल पर की है, वह अच्छी है और उस से किसान को एस्योर्ड दाम मिल जाते है। इस तरह से इस मे काफी अच्छा सुधार हुआ है और आज हालत यह है कि इतना गन्ना है कि उस की पिलाई नही हो सकेगी अगर लम्बी देर तक मिलो को चलने के लिए नही कहा जाएगा। अगर आप मिलो को लम्बी देर तक चलाएगे तो एक सुझाव बहुत गम्भीरता पूर्वक मैं देना चाहता हू। बाद मे चल कर गन्ने का रस कम हो जाता है और चीनी की परसेन्टेज कम हो जाती है। तो ऐसे वक्त मे जैसा कि आप ने मिल जल्दी चलाने के लिए कुछ रिबेट दिया था और मिल जल्दी चले उसी तरह से इस रिबेट को एण्ड मे भी देने की आवश्यकता है। अगर कई दिनो तक मिल चलेंगे तो किसानो का गन्ना खेत में नही रहेगा और किसानो को उस के गन्ने का दाम मिल जाएगा। इस का यह असर होगा कि अगर साल भी आप के गन्ने की प्रोजक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हरेक चीज को ध्यान मे रख कर कि किस वक्त क्या परिस्थिति है उस के अनुसार पालिसी डिसिजन लेने की जरूरत है जिस से कि मिल वालो का काश्तकारो का और कन्ज्यूमरो का सब का फायदा हो।

जो बात इस प्रस्ताव में कही गई है चाहे डिटेल्स मे हमारे और उन के विचारो मे सहमति न हो लेकिन इस मे जो दिशा निर्देशन दिया गया है उस की मैं सराहना करता हू। मैं बहुत आभारी हू कि आज हम कई बातो पर घंटो चर्चा कर रहे है और इस चर्चा मे हम बहुत सी बाते कहेंगे और बहुत सी बातो को हम सुनेगे (घंटी) मैं दो एक मिनट मे समाप्त करता हू। मैं ज्यादा समय नही लूगा क्योकि मैं समझता हू कि बहुत से लोग इस पर अपने विचार प्रकट करेंगे और सब के विचार सुनने की आवश्यकता है। मैं इतना ही आप से निवेदन करना चाहता हू कि ऐसे मुद्दो पर हम लम्बे चौड़े झगड़े न उठा कर एक एक प्वाइन्ट को ले कर चले, तो हम काफी गम्भीरता से चिन्तन कर सकते हैं। इस चीज को सामने रखते हुए हम कुछ खास बातें आप के सामने रख सकते है और एक रास्ता बना सकते है। हमारा आगे का प्राइस स्ट्रक्चर क्या हो आगे का मार्केटिंग सिस्टम क्या हो और उस मे प्राइसेज का फ्लक्चुएशन क्या हो—आप ने जैसे 15 परसेंट की बात कही—कितना परसेन्ट साल मे फ्लक्चुएशन हो प्राइसेज मे कितना उतार-चढाव हो कन्ज्यूमर्स को वाजिब दाम पर चीज मिले प्राड्यूसर्स को वाजिब दाम मिले और मार्केटिंग मे बीच वाले को भी रीजनेबिल मार्जिन हो इन सारी चीजो को देखने की व्यवस्था हो और इन पर गम्भीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है। मैं इस प्रस्ताव की बहुत सराहना करता हू क्योकि हम को कुछ कहने का मौका मिला है। यह एक व्यापक सवाल है। इसलिए कोई एक मंत्रालय इस पर कुछ नही कह सकता है। आप को इन सारी बातो को सोचना है और सब मंत्रालयो का समन्वय कर के ऐसी कोई स्कीम या योजना बनानी है जिस से सब लोगो को फायदा हो।

गेहू के बारे मे कल जो घोषणा की गई उस के बारे मे पहले क्या था और अब क्या है, इस पर कुछ लोगो की अपनी भावनाए है। मैं इस समय उस प्रश्न मे नही जाना चाहता और इस मामले को इस के साथ नही जोड़ना चाहता पर एक प्रेक्टिकल बात मान कर आप ने एक रास्ता निकाला और आज के हालात के अन्दर मैं सोचता हू कि हमे किसी एक डागमा के अन्दर नही चलना चाहिए और यह नही कहना चाहिए कि यह नही हुआ और वह नही हुआ और यह नीति सही है और वह नीति सही है। प्रेक्टिकल रूप से और समझ-बूझ कर हालात को देख कर हमे कोई बात करनी चाहिए। इसलिए आज मैं इस वक्त इस झगड़े मे नही पड़ना चाहता पर मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हू कि इस वक्त के हिसाब से जो सोचने का सवाल है तो उस मे हम

[श्री नाथू राम मिर्धा]

ने किसानों की बात भी सोची है जो अपोजीशन करते थे और अपना फेस्ट्रेशन शो करते थे। उन की बात को भी हम ने सोचा है और काफ़ी कन्ट्रोल भी इस मामले में रखा है। इसलिए जो यह फैसला लिया गया है, वह अपने आप में एक महत्व रखता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह एक बुनियादी सवाल है और पांचवीं योजना की पृष्ठभमि में जो लक्ष्य आप ने निर्धारित किये हैं, उन को अगर आप एचीव करना चाहते हैं, तो इस प्रस्ताव में दी गई भावना के ऊपर आप को गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा और जिन कुछ बातों पर आप ने फैसला ले लिया है, और जिन को आप ने पांचवी योजना में लिखा है, उन को कारगर ढंग से लागू करना होगा और सही ढंग से संगठन को चलाना बहुत जरूरी होगा। तभी जो आप का पांचवी योजना का लक्ष्य है, वह एचीव हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Sir, I want to read out my amendment :

Add at the end,

"the Government should establish its decisive command over the production and distribution of vital agricultural commodities and agricultural inputs;

and therefore, recommends nationalisation of Sugar Industry, raw jute trade, fertiliser production and distribution and distribution of diesel and kerosene oil with immediate effect."

Shri Limaye has mentioned about growth of agriculture. I maintain that unless there is true and effective land reform in the country, there cannot be any growth of agriculture. That is the first requirement. I would deal with certain items of inputs as well as outputs. Both these vital sectors are mostly in the hands of unscrupulous traders, hoarders, profiteers and black-marketeers. The middle and small peasantry are exploited while they buy their requirements and again they are exploited when they sell their commodities. Take fertilisers. I have asked time and again why in a country where the per capita income is the lowest in the world, the poor peasant has to pay the highest price for fertilisers. In Ceylon, per tonn of ammonium sulphate, the price is Rs. 1583, according to the information I got from the Ministry on the 6th March, 1974, which is the latest figure I have.

17.00 HRS.

In India for the same commodity you pay Rs. 2,665. Take another very vital commodity, urea. The prices are : USA Rs. 1,470, Ceylon Rs. 1,185 and India Rs. 2.085. Why should it be so ? Take a country like Australia, where the *per capita* income is very high, where the peasant is very affluent. There a man is required to pay Rs. 1,688 for a tonne of ammonium sulphate while a peasant in India will have to pay Rs. 2,665. Similarly, in New Zealand, another affluent country, the farmer will pay Rs. 1,793 while we pay Rs. 2,665. For every item of fertilizer we are paying a much higher price. Why is it so ? Is it because you have completely surrendered yourself to the private sector monopolists, both foreign and Indian ? Is it not a fact that you have allowed them complete freedom in the matter of price fixation ?

Then, what are the profit figures ? Or let us take the utilisation of installed capacity. In the public sector it is 28 per cent while in the private sector there are plants where it is as much as 95 per cent. Are you playing into their hands, Shri Dhar ? How can you explain and justify this ? Shri Shahnawaz Khan tries to justify things in his own manner, which is not understandable to us. I do not read his language.

Take the Gujarat Fertilizer Company, which is not a public sector plant but in the private sector. The gross profits as on 31st March 1972, after providing for development rebate and reserves is Rs. 807 lakhs and the net profits come to Rs. 374 lakhs. In the case of Coromandel Fertilizers, after taxation it comes to Rs. 455 lakhs as on 31st December, 1972. It is a wonderful example of socialism and *garibi hatao* of your party. Then comes the Indian Explosives, owned by British monopolies, very good people, who were installed in power here.

The profits of the private sector before tax for 1970-71 was Rs. 1,091 lakhs. In 1971-72 it rose by 50 per cent and reached Rs. 1.529 lakhs. Every year it is jumping up. That is why every small peasant and the middle peasantry in our country have to get their requirements of fertilizer at a controlled price, which is the highest in the world. Even that controlled price is not strictly enforced. When the controlled price for 50 kg is Rs. 52, in some areas a farmer has to pay as much as Rs. 200. Not only that, in most of the cases the fertilizer is either sub-standard or highly adulterated. So, you are beyond cure. Shri Madhu Limaye talks of the Chinese pattern. But I am not living in a fools' paradise or a castle in the air. I know you people will never do it because you belong to the monopolists.

Then I come to the lack of supply of balanced fertilizers. Your own report says—perhaps, you are not aware of it,—in 1970-71 from the Central pool supply of 1.6 million tonnes of fertilizers, only 17 per cent were in complex form. Can you explain that to us?

Now I come to another item, pesticides, a very small requirement. Why is the consumption of pesticides so low? I quote:

> "Indian die contains 0.27 (m.g.) of D.D.T., said Dr. M. K. Mazumdar, Chief of Presidency division at the Central Food Technological Research Institute in Mysore. And the level of D.D.T. in body of an Indian is the highest in the world although per hectare consumption of pesticides is much less here compared to the USA or Japan."

Why is it that the use of pesticides here is so low?

SHRI D. P. DHAR: It shows that the pests are less here.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: That the pests are having a time they never had before. The gentlemen sitting opposite to us, if you don't mind it, I would describe them to be a social pest.

Further, I quote:

> "Apart from the lack of knowledge about handling such pesticides which have often led to serious ailments among farmers and consequently they have become superstttious about their uses, the demand has also fallen due to the recent withdrawal of the subsidised sale of pesticides."

There is no propaganda; there is no availavility of inputs to small and middle peasantry.

Then, there are a lot of shady deals. I will not go into them.

About diesel, Mr. Madhu Limaye has very clearly said—Mr. Mirdha also said it—that you are not able to give diesel, electricity and water for minor irrigation even today, after 27 years of rule, and does not exceed, to my knowledge—I am subject to correction—22 per cent of the cultivated land in the country. That is your performance. Even till last year, you could not spend the whole amount for spending in the drought-affected areas although you are all the time delivering speeches and sheding crocodile tears.

Coming to seeds, what is the performance of the National Seeds Corporation. It is on the honours list. It is a wonderful performance. Half of the seeds do not germinate. It is seething with corruption.

About electricity, my hon. friend has just now mentioned that you are reluctant to give cheap electricity to peasants but you are very generous to other people. There was a paper report that you promised to pay Rs. 10 crores to the Calcutta Electric Supply Corporation. You have not contradicted the report although you said, no. It does not convince me. The D.V.C. sells electricity at the rate of 6.75 p. per unit and the British monopoly concern fleeces the poor consumer and charges even upto about 20 p. per unit When Mr. Limaye brings forward a Resolution that you give electricity at the rate of 10 p. per unit, your heart starts beating very fast You only feed monopolists.

About aluminium, do you know—you must be knowing because your party moves with the affluence of others—that 75 per cent of the production has gone to the black market and is being sold at more than 400 per cent the controlled price?

[Shri Jyotirmoy Bosu]

You know all about it. But you do not want to touch it. Because touching them will mean that you will be out of power. You give them cheap electricity; you allow them to do black marketing and you allow them to fleece the poor consumers and the workers as much as they can.

About the credits to the farmers, the present norms of lending and interest-rate should be changed. A small man in the rural areas, a middle-cadre man in the rural areas, cannot meet your requirements. He cannot afford to pay what you want. If you want real intensification of agriculture, you have to take a deep look at it.

There was a survey conducted by the Chandigarh University that 90 per cent of the bank credit that is now being given is going to the rich peasantry. The small peasantry has to depend on village moneylenders or Congressmen who are *kulaks* in the villages. In the course of years, they become bankrupt and they lose all things they had in the world

Then there is the question of exploitation on outputs Thanks to Prof. D. P. Chattopadhyaya, Professor of Philosophy, University of Jadavpur, he has been very successful in collecting funds for the party. Of course, that was the understanding. (*Interruption*) Mr. Ram Gopal Reddy, you can interrupt me when I talk about sugar and not now. Now I am talking about jute. The jute yield is about 60 lakh bales a year. And what is the performance of the Jute Corporation of India? I cannot pronounce it properly. It is *joot* Corporation of India. The J.C. I has, so far, been able to purchase a little over 1 lakh bales. Do you know why? It is because, if they really expanded their business activities, then the money collection will be curtailed. Do curtail the public sector activities; it will be much easier for the other to make hay:

There is a beautiful editorial which says:

"Thanks to this year's bumper crop, the total availability of jute is likely to exceed the demand of the mills by almost 19 lakh bales. This has already depressed raw jute prices, and thus greatly harmed the growers while conferring a bonaza on traders and speculators ... The prices have declined further from Rs. 53 a maund to Rs. 51."

Good luck for those who are with Dr. D. P. Dhar and his company.

The Agricultural Prices Commission has said very clearly certain things:

"Side by side this measure, the structure of marketing specially in the eastern region needs to be improved. Although legislation for the establishment of regulated markets has been passed in all the jute-growing States except Assam .. "

I do not know why it has not been done in Mr. Chairman's State. That explains why the Congress is coming in bigger numbers.

" . except Assam, the enforcement of the Act is still wanting in almost all the States."

"Even where the markets have been regulated, the enforcement of the provisions of the Act continues to be poor."

It has to be kept poor in the class interests of the ruling class.

I may tell you on my own responsibility in the House today that, last year, the jute people—I am not talking about growers because they have to give a pound of flesh from their body every year—have made an additional profit of Rs. 200 crores in one year. There is not the slightest doubt about it; nobody will dispute that. How has the price index come down? That is also a matter. Do Government really bother as to how a handful of people are taking a chunk of flesh from millions every day? They are not interested in that.

Cotton position is also equally disturbing The Cotton Corporation of India is another creation of Mr. Lalit Narain Mishra; his nominee was installed there; I do not want to go into it any further because we have known him for years.

"The Cotton Corporation of India has virtually missed the bus in its indigenous cotton procurement drive in the current season. Practically half the season is over and about 25 lakh bales out of

an estimated crop of 60 to 62 lakh bales have arrived and been absorbed by the market. Yet CCI's purchases to date amount to hardly two lakh bales against a target of 29 lakh bales."

MR. CHAIRMAN : Many speakers are there. Please try to conclude.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I am just trying to conclude.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) I want to know whether this discussion will conclude at 6 O'clock or it will continue.

MR. CHAIRMAN : The discussion is to end at 6-10 P M Two hours were allotted by the Business Advisory Committee, but if the House decides to extend it, we shall have to extend it and continue with this Private Members' Business till 6-40 P M today

SHRI JYOTIRMOY BOSU . Then it says

"Sources close to the Corporation say that there are vested interests operating at the top of the corporation's hierarchy which want to invest a major portion of the balance amount in the Punjab region."

etc etc.

The whole thing is about vested interests. And, Sir, another very interesting item is this. It says .—

"Cotton traders in Vidarbha are happy that the State Government has suspended the monopoly purchase of cotton Hundreds of those who had folded up their shops—in Amaravati. Akola, Yeotmal and Buldana districts—will soon be back in business with a bang. Indeed some of them have been celebrating the event by distributing sweets in public places"

This is another Congress Government performance in Maharashtra.

And, Sir, in respect of textile mills, in respect of those who live and serve on the blood and sweat of the cotton-growers, if you take into consideration the profits that they have made in the year 1973, if you study the share market report of Bombay in the year 1973, you will see that something has happened which is unprecedented in the history of this country. Take Mills like Birla's Century Mills, mills like New Shorrocks, etc. Their equity prices have just appreciated by 140 per cent in one year.

Sir, I conclude. Before that, I must refer to one item which is important, namely, Sugar Sugar in this country unfortunately tastes bitter The malpractices are very deep-rooted. Mr Maurya is looking at me I hope he knows about all this. I am sure he knows about this, he is Minister in charge of Sugar, I am told There is manipulation at the recovery level to the tune of even 25 per cent. Now, they were getting trouble from all the Excise inspectors So they had to remove all the Excise Inspectors, and revert to S R P., that is self-removal profits, they are working on sales, they are cheating to the tune of 25 per cent and generating black money.

There is the *Economic Times* write-up-this is really something indeed which I cannot resist quoting. It says :

The sugar industry had an unprecedented buoyancy in profits and profitability during 1972-73 While the pre-tax profits more than doubled during the year under review, the profitability both in terms of sales and total capital employed reached new peaks '

Then it says

"Some of the sugar companies which recorded unprecedented rise in profits before tax during 1972-73 are Andhra Sugar (from Rs. 95 lakhs to Rs 214 lakhs)"

—I can understand Mr. Ram Gopal Reddy's anxiety —

" Deccan Sugar (from Rs. 160 lakhs to Rs. 136 lakhs) Sakthi Sugar (from Rs 35 lakhs to Rs. 105 lakhs). Gobind Sugar (from Rs. 7 lakhs to Rs. 87 lakhs). Ugar Sugar " etc. etc

And, Sir, profits in sugar is a limitless item. It is done because the ruling party wants that the sugar tycoons should be allowed to make money and a part of that should be passed on through—am I permitted to name, the treasurer of the Indian National Congress, Mr. Uma Shankar Dikshit, for the holy purpose that they are perpetuating here ...

[Shri Jyotirmoy Bosu]

And then, I ask Mr. Maurya about this. I had put a question to him where I asked him about the contents and I further asked, why is it that the Sugar Commission's Report had not been laid on the Table of the House.

It is very strange indeed. The reply is :

"The Commission has submitted its final Report on 27-2-1974 and it is under examination."

Now, I want to ask : why it is that as soon as the Commission's Report was submitted, that was not placed on the Table of the House and circulated to the hon. Members ? Why is it that there is no uniform standard adopted ? When the Pay Commission's report was submitted, within three or four days, the same was placed on the Table of the House and circulated to Members That was another issue. Here is an issue and they have given grand protection to the monopolists and tycoons. And so, the report should be kept in cold-storage for as long a time as possible. Mr. Maurya, you should tell the House here why you have not changed your attitude with regard to this report and why you have not placed this report on the Table of the House without any hesitation. What I want to know from you is this. Is it a fact that the Sugar Industry Inquiry Commission has recommended nationalisation of sugar Mills ? Is that the reason why you are hiding this report from us for so long a time ? I want to know about all these things. On top of it—it is a shameful thing—I do not know whether the information is correct or not, the sugarcane growers' dues till 30th September, 1973 amounted to Rs. 6.65 crores. This is another shameful thing—why is it that the tycoons collected finances from three sources, that is, those who supply, in between the bank and those who buy. From these three sources, they are getting finances. For the two sources, they do not have to pay any interest. I want to know why this is being allowed and what is the present position in regard to this :

Now about wheat, may I know why the corrupt Government have somersaulted ? Why have they gone back upon their position ? I do not know what they have done with regard to the documents which they have created in Ahmedabad Congress. They must have thrown it in Sabarmathi. That was because that document has created a bad name for Shri Dhar or Mrs. Gandhi. Can you imagine why are they going back upon this ? Why should the wheat trade be given again to the profiteers, traders and blackmarketeers ? In Northern India alone, last year you paid Rs. 1.50 per kilo for wheat. You will be required to pay nothing short of Rs. 5/- a kilo of wheat in my part of the country. It may fetch anything between Rs. 6 and 10/- I do not know. I have to ask one question more. Shri Gujral is not here. He produced 20 to 25 documentaries—I am told—each documentary costing about Rs. 1 lakh on wheat trade take-over What has happened to the documentaries ? Will they be sold by auction or what are you going to do about them

Sir, I support Shri Madhu Limaye's Resolution. But, I think, we are living in fools paradise by this sort of ideas. This is nothing but the government for the monopolists, through the monopolists and to the monopolists sitting opposite!

MR CHAIRMAN Now I would remind the hon. Members that after the Private Members' Bills, there is half an-hour discussion I would like to have the opinion of the House whether they would like to take up the half-an-hour discussion at 18-40 hours. Or does the House decide that this discussion may be postponed to some other day ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH) : I have spoken to my hon. freind as well as the Minister. They have agreed. The House may agree now to take it up on the 5th.

MR CHAIRMAN : What is the view of the House ?

SEVERAL HON. MEMBERS : It may be taken up next time.

MR. CHAIRMAN : So, the House agrees that the half-an-hour discussion may be postponed till an appropriate date is fixed by the Government.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : सभापति जी, जो प्रस्ताव श्री मधु लिमये का सदन के सामने विचारार्थ है इस प्रस्ताव से शायद ही कोई आदमी असहमत होने की हिम्मत करेगा। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इसमें कोई शक नहीं। जो बातें इस प्रस्ताव के जरिए से चाही गई हैं वे अपने आप में ठीक हैं और आवश्यक हैं। परन्तु दुर्भाग्य से जो इस देश की मौजूदा शासन व्यवस्था है उसमें इन सब बातों को पूरा करने के लिए बहुत बड़े इरादे, बहुत अच्छी मशीनरी जिसका इरादा हो जिसका विश्वास है इन कार्यक्रमों में उसकी आवश्यकता है। आज जब कि मुल्क में कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, हर रोज कीमतों के बढ़ने का सिलसिला जारी है पिछले साल से 26 परसेन्ट कीमतें बजट आने से पहले बढ़ गई थीं और बजट आने के बाद भी कीमतों में वृद्धि हुई है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। लोग आम जरूरत की चीजों को मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जबकि यह मुश्किलात हैं सरकार ने कोशिश की थी कि कुछ चीजों के व्यापार को अपने हाथ में ले, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार उसमें भी अपनी असफलता स्वीकार करती जा रही है। खाद्यान्न की जहां तक बात है, हमने पिछले वर्ष फैसला किया था कि हम चावल मिलों और चावल का व्यापार भी अपने हाथ में लेंगे। चावल का व्यापार तो अपने हाथ में लिया नहीं, उसको लेने में हम कतरा गए लेकिन गेहूं का थोक व्यापार हाथ में लेने के बाद अभी कल ही खाद्य मन्त्री का वक्तव्य पढ़ा तो उसमें बहुत निराशा हुई। वे अपने पहले के कदम में पीछे हटे हैं। दूसरी ओर उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। फैयर प्राइस शाप्स के लिए उन्होंने 125 रुपए का रेट रखा है जो इस बात का द्योतक है कि सरकार अमल में कीमतों को रोकना नहीं चाहती है या उसमें मजबूती नहीं है और वह कीमतों को बढ़ने से रोक सके।

प्रोक्योरमेंट की बात करें तो हमारे अपने राज्यों में कितना प्रोक्योरमेंट हुआ है, मोटे गल्ले को देख लें, चावल और गेहूं को देख लें, यह सारी की सारी स्थिति और उसके साथ साथ वितरण की बात हम देखें, वितरण हम करें ड्योढ़ी कीमत पर, यह बात मेरे मित्र लिमये जी ने अपने प्रस्ताव में कही है लेकिन वितरण करे क्या ? जो वितरण करते हैं उसमें क्या देते हैं ? फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया के बारे में एक दफा नहीं अनेक बार यह कहा गया कि उसका इन्तजाम ठीक किया जाये। जो गल्ला या जो चीजें फूड कार्पोरेशन के जरिए से मिलती हैं, पता नहीं वह कहां से आ जाती है ? मैं गांव का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि किसानों से फूड कार्पोरेशन वाले ठोक बजा कर गल्ला लेते हैं। क्वालिटी के नाम पर जब तक उनको कुछ प्राप्ति न हो तब तक अच्छा कीमत भी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन फिर पता नहीं कैसे कूड़ा कर्कट और न मालूम क्या क्या मिला हुआ गल्ला वह देते हैं जिसको शायद जानवर भी नहीं खाते। वहां से फूड कार्पोरेशन के गोदामों में वह गल्ला आ गया भगवान हो जाते।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अमल में इस प्रस्ताव की भावना और मंशा में सहमत होते हुए भी मुझे लगता है हम सब मजबूर हैं इस तरह के प्रस्ताव को अमल में, कार्य रूप में लाने के लिए। आप किसी भी चीज को देखें हम कहते हैं कि हम गरीबों को सस्ता कपड़ा देंगे, आवश्यकता के अनुरूप मोटा कपड़ा देंगे लेकिन आवश्यकता की बात आप छोड़ दीजिए आपने सिक मिल्स कार्पोरेशन जो बनाया है जिसके जरिए से आपने करीब करीब 100 मिलें ले ली हैं उनमें आप मोटे कपड़े का उत्पादन नहीं करते। उनके जरिए से आप लोगों की जरूरत को पूरा नहीं करते। हो यह रहा है कि आज सवेरे मधु लिमये जी ने प्रश्न किया था जिसके जवाब में विज्ञ मंत्री जी ने कहा था कि हम सोच रहे हैं कि 10 परसेन्ट से बढ़ाकर 50 परसेन्ट तक मोटा कपड़ा इन मिलों के जरिए से हम उत्पादन करें।

[श्री नवल किशोर शर्मा]

पता नही सोचने का क्रम कब तक इस मुल्क मे जारी रहेगा । लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि जब हमारे देश मे मोटे कपडे का उत्पादन हो सकता है, उसके लिए रूई का उत्पादन होता है, उसके लिए आवश्यक मिले हैं लेकिन हम करते नही हैं । पहले व्यवस्था थी कि हम उन पर थोडा बहुत जो मिले उत्पादन नही करती मोटे कपडे का उस नियम के अनुसार उन पर जुर्माना कर दिया करते थे । जर्माने की सजा इस देश म अब एक रेस्पेक्टेबिल सजा हो गई है, उस को कोई पूजीपति या व्यापारी सजा नही मानता है । बल्कि आज कल तो उन्होने जेल जाना भी अपना धर्म मान लिया है । जैसे राजनीतिक लोग जेल जाने को अपना सर्टिफिकेट मानते हैं, वैसे ही इन लोगो ने मानना शुरू कर दिया है ।

अब उन्होने पिछले साल घोषणा की कि म्यूचअल ऐग्रीमेंट के जरिये मे उन पर यह दबाव डाला जायगा कि मोटा कपडा बनाया जाय । पता नही कितना उत्पादन हुआ ? माननीय मौर्य जी बैठे हुए है चीनी के मामले में अजीब नीति और तरीका है, और उस के लिये दलील दी जाती है कि किसान को ज्यादा कीमत देना चाहते है गन्ने की इसलिये हम व्यापारी को ऊची कीमत पर बेचने की छूट देते हैं । आप ऐसा क्यो करते है ? आप अगर यह समझते है कि किसान को उस की उचित कीमत मिलनी चाहिये और वह कीमत इकोनामिक टर्म्स मे इतनी होनी चाहिय, तो आप उतनी कीमत दीजिये । यह है कि शुगर मिलो को अनापशनाप क्या तरीका फायदा उठाने की इजाजत दी जाय ।

इसी तरह से वनस्पति को देखिये । उस क्षेत्र में भी यही हो रहा है । पिछले दिनो आधे घटे की चर्चा थी हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के मामले में, डालडा के बारे में । इस कदर उस कम्पनी ने भारत में फायदा उठाया है, कौन नही जानता है । लेकिन यह सब जानते हुए भी पता नही क्यों हम कारगर कदम नही उठा पाते है ? और अगर उठाते है तो ऐसा लगता है कि सरकारी मशीनरी उस कारगर कदम को उठाने मे सरकार के रास्ते मे बजाय सुभीता दिलाने के रोडा अटकाती है । एक नही अनेको कदम सरकारी अधिकारियो द्वारा उठाये जाते है, काम करने वाले लोगो के द्वारा उस नीति के विरुद्ध काम किया जाता है । कितने अधिकारियो को इस नीति के विरोध मे काम करने के सिलसिले मे आप ने दडित किया ? एक को भी नही ।

तो इस प्रस्ताव की भाषा और मशा से सहमत होते हुए भी, मैं यह मानता हू कि जब तक इस भाषा और मशा के लायक हमारे देश मे सरकारी तत्र नही होगा जब तक वह तत्र हमारी घोषित नीतियो के अनुरूप काम करने की क्षमता और योग्यता तथा इरादा नही रखेगा तब तक देश का कल्याण नही लाने वाला है । मैं डागा जी से सहमत हू कि 26 साल मे हम उस को ठीक नही कर सके, मुझे भी अफसोस है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि हम सब चाहते है कि किसान को उचित दामो पर खाद मिले । लेकिन मिलती है क्या ?

खाद की स्थिति क्या है, खाद का वितरण कैसे होता है ? जो प्राइवेट मिल ओनर्स हैं वह खाद अपने एजेन्टो के द्वारा बेचते हैं । और उन एजेन्टो को बेचते है जिन से पहले प्रीमियम अपनी जेब मे ले कर रख लेते हैं । सीमेंट की भी यही बात है । एक नही अनेक मामले मे जिन मे प्राइवेट डीलर्स यही करते है और जब प्राइवेट डीलर्स को प्रीमियम के आधार पर खाद मिलेगी तो स्वाभाविक है कि वह ब्लैक मार्केट में बिकेगी । तो किसान महरूम रह जाता है ।

बिजली की भी यही दशा है । उद्योगपति को आप एक पैसे से तीन पैसे प्रति यूनिट से बिजली देंगे और उस से ऐग्रीमेंट करेंगे 15 से 25 साल के लिये । लेकिन किसान को आप 10 पैसे प्रति यूनिट में भी नही दे

सकते। किसान को जब बिजली देने का सवाल आता है तो गांव में क्या होता है कि रात को किसान को बिजली दी जाती है। किसान को कड़ाके की सर्दी के अन्दर बिजली दी जाती है और उस को कहा जाता है कि रात के समय खेत में पानी दें। लेकिन मिल मालिक को बिजली उस के एयर कंडीशनर के लिये दूसरी सारी सुख सुविधाओं के लिये दिन में देंगे, ऐशो इशरत के लिये देंगे। हमारे सोचने और काम करने का तरीका इस ढंग का नहीं है, सारे सेक्रेटेरियट में नहीं है, लोग इस तरह से सोचते हैं कि उन को कोई मतलब नहीं है गांव में रहने वाले लोगों से, गरीब आदमी से कोई मतलब नहीं। उन को अपनी सुख सुविधायें चाहियें और इसी तरह से उन का कोल्यूजन है उन बड़े लोगों से। इसलिये जितने भी प्रस्ताव हम करें, अच्छी बातें कहें, वह सब निरी कल्पना रहेगी, भावना रहेगी। मैं समझता हूं अच्छा हो अगर हमारे देश के नेताओं को शक्ति मिले और वह मजबूती से काम करें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Mr. Chairman, Sir, the resolution moved by Mr. Limaye raises very many important issues which are vitally concerned with our economic development and the standard of living of our people. My only apprehension is that it raises too many issues which may give our very erudite Minister the opportunity to be equally vague and diffuse when he replies. Anyway, I think the essence of what Mr. Limaye's resolution tries to put forward is the question of the pricing policy of this Government, and I hope that the Minister also, when he replies, will try to explain to this House what exactly is the philosophy of the Government behind its pricing policy, whether it be the prices of agricultural commodities or industrial goods or the relative ratio between the prices of the different commodities and so on.

Sir, I am sure that the Planning Minister himself—I do not know whether he is prepared to admit it in the House—is quite perturbed over the fact that the plans for which his Ministry and the Planning Commission are responsible, are in danger of being completely scuttled by this galloping inflation which has overtaken our economy. It is impossible to plan anything even one year ahead now, even six months ahead—let alone a five year Plan—in the face of this unpredictable and unprecedented rate of inflation which has now taken hold of the economy.

So, I would like to know from him whether the pricing policy—if there is such an overall pricing policy and I doubt it very much—but if there is such a thing in the Government, whether it is meant further to stoke the fires of inflation or whether it is meant within some reasonable period of time to have a disinflationary impact on the economy. What exactly are they thinking? That is what I would like to know.

This resolution fortuitously has come forward for discussion just at a time when a very inauspicious event has taken place as far as the people of this country are concerned. I think Mr. Limaye did not know himself that this particular day on which the ballot has favoured him to bring forward this resolution would practically coincide with the Government of India's decision to reverse its policy of nationalisation of the wholesale trade in wheat. We are going to debate this, I am told, more exhaustively next week perhaps, but as far as the impact on pricing policy is concerned, what exactly is it going to mean, I want to know. The statement made here by the Minister of Agriculture yesterday was quite explicit in the sense, that it says that under the new policy, the traders will be allowed to purchase any amount of wheat they like provided 50 per cent of their purchase is handed over to the Government and the remaining 50 per cent can be sold by them at any price they choose anywhere in the country. Last year the procurement price was Rs. 75 per quintal. Many people criticised that it was too low to act as on incentive for the farmer. Many persons were pleading that an increase even Rs. 8 or 10 would help to bring in larger quantities of foodgrains. It was rejected by the Government at the time. Now under the advice of their economic

[Shri Indrajit Gupta]

experts and also the pressure of the majority of Chief Ministers, they have decided to fix the price at Rs. 105 per quintal. The last year's issue price of wheat to the consumers was Rs. 87 per quintal. In the open market it was selling at Rs. 2.30 per kilo. The Government itself is not going to purchase at the new price. It will be purchased by the traders and the price permitted to them is Rs. 105 per quintal. That will mean that the issue price to the consumer will be between Rs. 1.25 and Rs. 1.30 per kilo. I do not know what the price will be in the open market. It will be Rs. 5 or 6. The very good sentiments which are expressed in Mr. Limaye's Resolution presuppose something which unfortunately does not exist. I mean a real effective system of physical controls which just do not exist in this country.

What is the machinery by which you propose to ensure that 50 per cent of what is purchased by the trader will come to the Government ? You have given them a blank cheque. Practically to sell the balance of wheat at any price they like. I suggest that the present policy is actually not being determined by the Government at all. It is determined by the All India Foodgrains Dealers' Association before whom the Government has surrendered in the most abject and shameful manner.

As far as the other foodgrains are concerned, even last year when we were faced with resistance from vested interests, who did not desire to part with levies retreat began even from last year. It was decided not to interfere with the wholesale trade in other foodgrains. This is the basic commodity which determines the price of everything else. Unless the price of the basic foodgrain is brought down substantially or at least stabilised somewhere at some point it is impossible to expect the price of other commodities to come down or stabilise. This is the determinant factor and in this respect the Government has made clear in the last two or three days that they have given up this responsibility and surrendered to the pressures of the people who actually control the market. Therefore, what we are in for on this front is further spiralling of the prices and further inflation with all its consequent impact all along the price line.

I am unable to understand this. They say that this is a planned economy; they say also that the price is fixed. They announce that this is the price; this should be the price; this is the controlled price. That way, we have known lot of pronouncements. But how are such announced prices are going to be implemented unless the Government has physical control, at least some amount of physical control, over the stocks of those commodities ? The prices are announced by the Government, but, stocks are held by somebody else who have nothing to do with the Government. How are the price controls to be implemented ? They have not been implemented and they will never be implemented.

In the case of edible oils, you fix the price. Edible oils are not in the Government's possession; stocks are not with them; stocks are with somebody else. We saw what happened in Gujarat. We see the condition of the edible oils market throughout the country today. But, from time to time, some prices are announced. For example, Vanaspati. Vanaspati prices are revised, I think, every month practically or every six weeks. Some committee is there, which sits down and because of the Vanaspati producers' claim that the cost of production has gone up because of the rise in the price of oils used in the manufacture of vanaspati, Government sanctions them a straight rise. But, the market is controlled by certain big producers of whom—my friend over there just mentioned—the glaring example is Hindustan Lever Company. The Hindustan Lever Company is after all only a branch or an off-shoot of a big international company—I do not know what call them a multi-national concern—Unilever whose operations in India are only a fraction of their global operations. Nevertheless, it is an off-shoot of the big international concern, Unilever. This concern in India is being allowed to go into so many types of activities. It is the biggest single producer of dalda and vanaspati in this country. Why can't their stocks be taken over ? Nobody is asking them to seize their stocks without paying them anything for it. Calculate the price, reasonable price that they should get, take over their stocks and

distribute them through your public distribution system. Why can't it be done? What is the difficulty? Mr. Dhar must explain to us. Why can't these commodities, whether it is coarse cloth or any other commodity, be taken over?

In regard to coarse cloth, we just now heard an announcement by the Ministry of Commerce that they have decided to give a 30% increase in price to the textile mill-owners provided they raise the total output of coarse cloth from 400 million metres to 800 million metres. But, I want to know, first of all, you have no machinery to enforce any of these things. We know, in the past, these mill-owners were quite willing to pay the penalities, which were prescribed, if any particular mill manufactured less than the prescribed quantity of cloth. They were subjected to a fine or penalty. They were quite prepared rather to pay the penalty than to manufacture the coarse cloth because it does not pay them; it does not give them the rate of profit which they want. They would prefer to divert the productive capacity to the fine and superfine varieties of cloth which give them roaring profits. Because that gives them so much profit, they can afford to pay the penalty to the Government for not having produced coarse cloth which the ordinary masses of our country, particularly in the countryside, the rural population, require. How are you going to ensure that this same thing will not happen now? Over and above that, this 30% rise has been ensured to the textile mills in the state sector, which have not been planfully taken over by the Government. More or less, they have come and fallen on the shoulders of the Government in the shape of what are known as sick mills or uneconomic mills or mills which have closed down. Government took them over, these hundred and odd mills, which are under the National Textile Corporation, and they provided a base, though an inadequate base, for the Government to see that production of coarse and medium varieties of cloth is really maximised at least in this sector. But, why can't this be distributed through the public distribution system? Must it disappear into the blackmarket? Must consumers always be told that it is not available unless they are willing to pay a premium under the counter. Why?

Then, Sir, same thing happens in ragard to sugar. I do not want to talk about this. Enough has been said here.

About kerosene. Kerosene is a petroleum by-product. Some quantity we are importing from the Soviet Union and so on and rest is being produced in our own refineries, whether they are public sector refineries or refineries of foreign oil companies in this country. The source of production is limited and easily identifiable. Why can't the stocks of kerosene be distributed through the public distribution system, instead of being handed over to dealers who are charging a premium for every litre. If things go on as at present, I can assure Mr. Dhar that not a single drop of kerosene will be available anywhere, because the total quota of kerosene production has been cut down by the Petroleum Ministry in order to provide larger quantities of furnace oil, diesel, etc. Proportionately the total production of kerosene has been reduced. The quota for different States has been reduced. Even this reduced amount of kerosene has to be made available to the consuming public through certain dealers and not through any public distribution system! Why? Why do you give scope to the people to indulge in profiteering, hoarding, blackmarketing etc.?

Regarding procurement of foodgrains, it sounds like a stale joke after the Food Minister's statement yesterday that we are practically giving up the wholesale takeover. Without procurement of the minimum amount required at least to maintain the public distribution system and save it from collapse and without takeover either of production or of the stocks of those industrial goods which are consumer necessities and distributing all of them through a public distribution system, I do not understand how there is any hope of holding the price-line in this country.

This discussion has come at a very auspicious time. Yesterday we decided to give up procurement practically and on Monday Mr. Dhar is going to launch the fifth plan. Raw jute is mentioned here. Rs. 157 per quintal was the support price announced here by the Government of India. It is not the price which

[Shri Indrajit Gupta]

would be paid to the primary cultivator but the price of raw jute at the mill gates at Calcutta. The derivative price which is deduced from this is what the cultivator is actually supposed to get. I think Rs. 157 per quintal works out to Rs. 53 a maund at Calcutta. But actually the cultivator in the villages has been selling the raw jute this year at Rs. 30 and Rs. 35 a maund. If you go round the countryside in West Bengal, it is common talk that in the next jute season, the cultivator has already made up his mind to plant paddy and not raw jute, because he has suffered very heavily this year, due to this bogus pricing policy which exists only on paper. I do not know what the whole machinery of the Jute Commissioner sitting in Calcutta is doing. The less said about the Jute Corporation, the better. It has totally failed It is a miserable organisation unable to set up purchasing producing agencies, unable to purchase, stock and transport jute. It is not able to produce even a ripple in the raw jute market.

As a result of this pricing, which has remained entirely on paper, the raw jute cultivators have suffered drastic losses, and they are saying that from next season they will not plant jute Why should they? It is more profitable to plant paddy. The result is going to be next year there will be a shortage of raw jute, the prices of raw jute will go up, the jute millowners will take advantage of it to say that their cost of production has gone up and, therefore, the export duties which have been imposed on sacking and hessain will have to be removed, the production must be restricted etc. and so we go round and round this vicious circle Then retrenchment will take place and wages will be cut We have seen it during the last few years

Lastly, there is the question of the relation of the bank credit policy to the pricing policy. I presume that different aspects of this should be part of one integrated policy. I do not think the Government deals with this in an integrated way. The different Ministries deal with different aspects of it in a compartmentalised way and so no overall integrated pricing policy, as an instrument of planning, can emerge.

It is being admitted by the Reserve Bank of India that a bulk of the bank credit is still being utilized for building up of inventories. What does it mean? It is only the use of polite language. I can quote from the report to show that a bulk of it is going to the commercial sector and is being used, not for productive purposes but for building up inventories, which is another polite way of saying that stocks are being cornered, stocks are being hoarded for speculative purposes, which leads to further price rise and further inflation.

So, I would say that the pricing policy is the hub of the question and none of the good things which Shri Madhu Limaye likes to have done by virtue of this Resolution can, in my opinion, be done unless the pricing policy of the Government is totally reversed, of which I have very little hope, and unless they take steps to actually get physical possession of stocks of foodgrains and essential commodities and see that they are distributed through the public distribution system at fixed prices. Without that there is no way of overcoming this crisis. I am afraid the Government seems to be letting down the country on that score

MR. CHAIRMAN: Before I call the next speaker, I want to inform the House that at about 6.10 the hon. Finance Minister will make a statement on the recommendations of the Third Pay Commission in respect of Class I Officers. After that the Minister of Education will make a statement on the proposed pay scales of university and college teachers.

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI (Lakhimpur): Mr. Chairman, there is no disagreement on the broad outlines and the principles of the motion moved by Shri Madhu Limaye. But this motion relates not only to agricultural pricing but to industrial policy and the distribution system and the overall socio-economic structure of our society. To my mind, such big things cannot be done by a simple Resolution. However, this motion provides us an opportunity to discuss the matter

and focus attention on the primary issues that are before the country today.

Before going into the details as enumerated under the six different heads, I would like to say something about the prices of agricultural products. It is stated that the prices of articles of common consumption should be one and a half times the cost of production. I would say that it should be much less. There should be only marginal profits, giving allowance for transport and other charges. There should not be any higher profit. Such a rigid formula should not be there.

18.00 hrs

The hon. Members who preceded me have spoken about the cotton imported from outside. Last year, there was a levy of 40 per cent on imported long-staple cotton. This created a condition for raising the price of good quality cotton which is produced in certain parts of our country. I am told—I have not got authentic figures—that the Cotton Corporations formed by the Government of India and the Government of Maharashtra made a good profit out of it. They sold cotton to textile mill-owners at a higher price and the textile mill-owners made a good profit on the plea that they purchased cotton at a higher price.

Today, we just now heard the Deputy Minister of Commerce making an announcement that there will be 800 million metres of standard cloth produced by the textile mills. What is this quantity as compared to the vast population of our country? We have got 55 crores of people. Leaving half a crore of people who may be considered as affluent people, 54½ crores of people are not affluent. If we do some arithematical work, it will be seen that only 1½ meters of cloth per head will be available to the people. Is this a good proposition? I wonder why there cannot be a rigid rule, a restriction, that no mill will be allowed to produce fine and super-fine varieties of cloth. Why cannot there be standardisation that only two or three varieties of cloth will be produced by the textile mills, 300 to 400 of them, in the country?

I have seen that those textile mills who produce certain quantity of standard cloth and release at a cheaper rate are allowed to sell fine and super-fine varieties of cloth at any price. There is no price control. According to the present policy, it is stated that there is a voluntary control. It is everybody's knowledge how voluntary control works. They make enormous profits to the tune of 300 to 400 times and even more than that. Therefore, if you want to bring satisfaction and equitable distribution of cloth to the people, there should be a complete ban on the production of this type of cloth. Only for export purposes, such cloth can be produced. It should not be allowed to be sold in the country. Then only, it will help the people. It will help curbing corruption also.

So far as jute is concerned, it has been said by my hon. friend, Shri Indrajit Gupta, that the price of jute purchased by the Jute Corporation of India at Calcutta is Rs. 157 per quintal. From my knowledge, I can say that the price of jute that is sold in Assam is less than about Rs. 100 per quintal. There is already a gap between the Calcutta price which is given by the Jute Corporation of India and Assam bottom

The Jute Corporation of India do not have their offices at the village level. They have got some offices in certain places. The Corporation allows the traders to purchase jute at any price from the growers and, later on, they purchase jute from those traders giving them Assam bottom price. Therefore, by establishing the Jute Corporation of India, the farmers and the growers of jute are not benefited. Only some persons employed in the Jute Corporation of India are benefited. The traders who deal in jute, in rural areas, are benefited.

Therefore, if you really want that farmers and growers should be benefited, instead of price support scheme, there should actually be a purchasing organisation which should purchase the entire quantity in certain regions at a certain price fixed by the Government for that commodity. Then only the growers will be benefited. Then only their purchasing

[Shri Biswanarayan Shastri]

capacity to purchase the commodities which are required for their household affairs will increase.

So far as electricity and fertilisers are concerned, some of the States are well-placed. But States like Assam and other States of the eastern region have no irrigation facilities, have less electricity and have no regular supply of fertilisers. It has been suggested in the Resolution that electricity should be supplied to the farmers who have holding of ten-acre and less at the rate of ten paise per unit. But I am of the opinion that ten acres constitute a high holding because in my State the maximum holding is 16 acres; nobody is allowed to have more than 16 acres of land in his name. Therefore, the figure should have been much lower. Again I consider ten paise to be on the high side because there are certain industries and big industrial houses which get electricity at two or three paise per unit.

I do not want to make a long speech But I would like to point out that what is needed at this hour is that the essential commodities, articles of common consumption, should be made available to the people of the country at reasonable prices. For that purpose, our Fifth Five-Year Plan should be re-oriented. It should be production-oriented, because unless production is increased, people cannot get things at reasonable prices; if there is no production, there can be no distribution at reasonable prices Then, along with production, we must aim at social justice. That should also be borne in mind.

I would like to say that the main drawback lies in the distribution machinery, the administrative machinery which is presided over by rotten bureaucrats. Due to the bureaucratic approach to the problem, the benefit does not reach the poor people, the common people, for whom it is intended. For instance, the take-over of the wholesale trade in wheat. It was a good policy; except for a few vested interests, nobody opposed it, but due to the bureaucratic machinery, due to the inefficient distribution machinery, that policy was not fully successful or that policy did not work as was expected. Therefore, that policy had to be reviewed and a revised policy had to be adopted. It only points out that unless bureaucracy improves itself, unless there is increase in efficiency, however good a policy may be, nothing can be achieved.

With these words, I thank hon. Member, Shri Madhu Limaye, for having moved this Resolution.

MR. CHAIRMAN : The time allotted for this Resolution by the Business Advisory Committee was two hours. We have already exhausted that time . . . . .

SHRI K. RAGHU RAMAIAH Since there are a number of members who wish to speak on this Resolution, the time may please be extended by two hours and the discussion may be resumed on the next non-official Resolution day.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar) : I would like to point out one thing. It is the convention of this House. Those Members who have given their amendments should be called first. It is the convention. I have seen it in the last sitting also.

MR. CHAIRMAN : I don't think so. At least as far as I know there is no convention that those who have tabled amendments should be called first.

Now, is it the pleasure of the House that we should extend the time for this Resolution by two hours ?

SOME HON. MEMBERS : Yes.

MR. CHAIRMAN : We will continue this on the next day.

श्री मधु लिमये : मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन दिन प्रति दिन प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस का समय हम काटते चले जा रहे हैं यह अच्छा नहीं है । आज ही आधे घंटे देर से शुरू किया ।

MR. CHAIRMAN : I don't think on any previous occasion we had postponed the Private Members' Business. I have asked for the decision of the House. Shri R. R. Sharma.

श्री राम रतन शर्मा (बांदा) : सभापति महोदय.....

MR. CHAIRMAN : You can continue on the next day when this business comes up for discussion; the next day of this discussion, for which time has been extended.

Now, the hon. Finance Minister.

12.12 Hrs.

STATEMENT RE. GOVERNMENT DECISIONS ON THE RECOMMENDATIONS OF THE THIRD PAY COMMISSION IN RESPECT OF CLASS I OFFICERS

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN) Mr. Speaker, Sir, with your permission, Sir, I rise to make a statement on the decisions taken by Government on the recommendations of the Third Central Pay Commission relating to Class I Central Services and posts and the All-India Services.

As the House is aware, the Commission had submitted its final Report to the Government on 31st March, 1973 and the Government announced its decisions on the recommendations relating to employees in Classes II, III and IV in October last. Government have now given due consideration to the recommendations relating to Class I Central Services and the All India Services keeping in view also the demands which have been made for making deviations therefrom, and have come to the conclusion that because of several factors, particularly the present economic situation and the repercussions on various Services, it is not possible to make any material changes, except a few marginal adjustments, in the recommendations relating to any particular service or category. Government have accordingly decided to accept broadly the recommendations of the Commission relating to the pay scales of Central Class I Services, Cadres and posts, subject to the following modifications :—

(1) In regard to the senior scale for the Central Services, the Commission has recommended a lower starting pay of Rs. 1050/- for some Engineering Services as also for Specialist Services like the Health Service, Economic Service, and the non-technical Services. In view of the existing senior scale of all these Services being the same at present and the administrative problems which would arise if two different minima as recommended by the Commission were to be accepted, Government has decided that the minimum of the senior scale of such Central Class I Services shall also be Rs. 1100/-.

(2) The period of restriction on the length of service for drawal of increments in the Junior Administrative Grade recommended by the Commission shall be removed.

(3) While the specific recommendations of the Commission for provision of a selection grade in certain Services shall be implemented, the principle of providing such a grade in various Class I Services has also been accepted, and the strength of this grade in each Service/cadre shall be determined after detailed examination review of the cadre structure, promotion prospects etc. in that Service/cadre.

(4) After considering the number and responsibilities of the posts of Heads of Departments in the Senior Administrative Grade, Government have accepted the recommendations of the Commission that the number of posts in the scale of Rs 2500 2750 may be raised to one half.

(5) The Cadre Review Committee will be requested to review on priority basis the cadre strength of the Central Services in order to improve, wherever necessary, the promotion prospects in various Services.

Government have also decided that recommendations relating to the All India Services too shall be accepted except that in the case of IAS there shall be no increase in the strength of the selection